Changing Ways

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

बदलती राहें

(साप्ताहिक)

वर्ष 01 अंक 16 पृष्ठ : 04 | मूल्य : 4 रुपये | धर्मशाला, 25 अप्रैल 2016 | हर सोमवार को प्रकाशित

सीएम ने माना प्रदेश में भांग व अफीम की खेती का सच

नशे के उत्पादन व कारोबार पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

कुल्लू। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिये मादक अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईएनएसए) द्वारा हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की समस्या, सच्चाई की तलाश एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) द्वारा वित्त पोषित तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के गृह विभाग, पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व विभाग, वन विभाग और नशा उन्मूलन से जुड़ी हुई प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी रही। सेमिनार का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया।

इस सेमिनार में हिमाचल प्रदेश के खासकर कुल्लू जिला में मादक पदार्थों के उत्पादन पर चिंता जाहिर की गई। सेमिनार में स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि हिमाचल में भांग और अफीम की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे अर्से से भांग की खेती एवं उत्पादन की गहरी जड़ें हैं। इसका लोगों की आजीविका से सीधा संबंध है और उनको आय का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि इसका संबंध हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से भी है। ये क्षेत्र काफी दुर्गम हैं तथा यहां पहुंचने में दिनों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भांग और अफीम की ही खेती होती है। उन क्षेत्रों में यह लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है।

नशे की खेती का विकल्प बनेंगे सेब

वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में इस समस्या से निपटने के लिए लोगों की आर्थिकी के लिए उन्हें केंद्रीय राशि प्रदान करके नकदी फसलों व फलों के उत्पादन जैसे विकल्प उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि लोग भांग व अफीम की खेती एवं उत्पादन से अर्जित होने वाली आय से अधिक कमा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में भांग एवं अफीम की खेती के लिए कुछ क्षेत्र जाने जाते थे, लेकिन विकल्प के रूप में इन क्षेत्रों में बागवानी विशेषकर सेब इत्यादि नकदी फसलों तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से कृषि व्यवस्था में बदलाव आया है और लोग अब अच्छी कमाई कर रहे हैं।

पड़ौसी राज्यों की स्थिति जिम्मेवार

हिमाचल प्रदेश में नशे के उत्पादन की सबसे बड़ी वजह पड़ौसी राज्य में नशे का बढ़ता चलन भी माना जा रहा है। हालांकि यहां विदेशी पर्यटक नशे को बढ़ावा देते हैं, मगर सबसे ज्यादा नशे की खेप पड़ौसी राज्य पंजाब में भेजी जाती है। इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिमाचल प्रदेश सरकार पर टिप्पणी कर चुका है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पिछले कुछ समय से नशीली दवाओं का सेवन एवं इनका व्यापार एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पड़ौसी राज्यों से अंतरराज्यीय तस्करी को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सीमा से लगते क्षेत्रों में ड्रग माफिया काफी सक्रिय है और हर हाल में इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

सिंथेटिक नशे के कारोबारियों का नेटवर्क भी खतरनाक

नशीले पदार्थों तथा युवाओं में इनकी प्रवृति जैसी समस्याओं का निराकरण करते समय अन्य बहुत सी बातों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। इनमें सिंथेटिक नशीले पदार्थों का वैध अथवा अवैध तौर पर उत्पादन कर रहे मादक उद्योगों, जो सुव्यवस्थित दिखते हैं तथा इनकी एक सुनियोजित एवं प्रयोजक विपणन व प्रचार रणनीति है। ये उद्योग इन पदार्थों की खपत के पैटर्न पर सतर्कतापूर्वक अनुसंधान करते हैं तथा नई-नई मंडियां विकसित करके नशीले पदार्थों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च तकनीकों को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तथा देश को बचाने के लिए इस प्रकार के नेटवर्क से निपटना होगा। यह बात स्वयं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाई है।

फेक्ट फाइल

भांग उखाड़ने व चरस पकड़ने के मामले

वर्ष 2011 में चरस तस्करी के 200 मामले सामने आए। इसमें 67 किलो 620 ग्राम चरस बरामद की गई। वर्ष 2012 में 156 मामले पकड़े गए। इसमें 38 किलो 120 ग्राम चरस बरामद हुई। वर्ष 2013 में 103 मामले दर्ज हुए और 60 किलो 69 ग्राम चरस पकड़ी। वर्ष 2014 में 103 मामलों में 86 किलो 984 ग्राम चरस पकड़ी। वर्ष 2015 में 90 किग्रा. चरस पकड़ी गई थी। इस साल यह आंकड़ा बढ़ सकता है। दूसरी ओर भांग की खेती का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2011 में 6770 बीघा, 2012 में 3930 बीघा, 2014 में 1603 बीघा और 2015 में 2000 बीघा तक भांग की खेती को पुलिस ने नष्ट किया था। इसके बावजूद पुलिस द्वारा चरस पकड़ने के मामले दर्शाते हैं कि पुलिस के इस अभियान का असर चरस के उत्पादन पर नहीं पड़ा है।

विश्वभर में एक करोड़ से अधिक की जान लेता है नशा

विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2013 के दौरान एक करोड़ 87 हजार मौतें नशीले पदार्थों से संबद्ध थीं। ये आंकड़े इससे भी कहीं अधिक हो सकते हैं। नशे की समस्या की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या से दोगुने के करीब आबादी नशे की चपेट में आकर मौत को गले लगा लेती है।

पहाड़ी ट्रैक्स पर नशे की हैंडलिंग करते हैं विदेशी

इस सेमिनार में विशेषज्ञों ने यह बात भी सामने रखी है कि कुल्लू के मलाणा, तोष व कसोल के अलावा जिला कांगड़ा के मैक्लोडगंज में नशे का कारोबार पहाड़ी रास्तों के जरिये सुरक्षित तरीके से किया जाता है। इसके लिए धौलाधार पर बने ट्रैकिंग रूटों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रूटों पर आम आदमी तो दूर पुलिस की पहुंच तक मुमकिन नहीं होती है। नशे के कारोबार में शामिल विदेशियों में इजरायली और रशियन मूल के पर्यटकों का बड़ा हाथ सामने आया है। साथ ही सप्लाई में नेपाली मूल के लोग भी सक्रिय तौर पर शामिल पाए गए हैं। इनके लिए पहाड़ी ट्रैक चढ़ना-उतरना आसान होता है। इसके अलावा प्रदेश में नशे के हैंडलर के तौर पर पड़ौसी राज्य पंजाब के लोग भी काफी संख्या में पकड़े जाते हैं। इन्हें सड़कों के रास्ते तस्करी करते हुए दबोचा जाता रहा है।

नूरपुर और चुराह में भी नशे का कारोबार

जिला कांगड़ा के नूरपुर और जिला चंबा की चुराह घाटी में भी नशे का कारोबार जड़ें गड़ाए हुए है। नूरपुर क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के लोग पहले देसी शराब बनाने का कारोबार करता था, मगर सरकार की बेरुखी और उन्हें इस कारोबार से बाहर निकालने की स्पष्ट नीति न होने के कारण इस समुदाय के लोगों ने पंजाब में फैले सिंथेटिक ड्रग्स के कारोबारियों को हाथ पकड़कर स्मैक/हेरोइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी है। वहीं जिला चंबा के चुराह में भी कुल्लू की तरह ही चरस की खेती होती है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठीन और जम्मू-कश्मीर के साथ लगते क्षेत्र के कारण चरस का कारोबार गहरी जड़ें फैलाए हुए है। पुलिस चरस तस्करों को तो दबोचती है, मगर उत्पादन पर चोट नहीं कर पा रही है।

नशा रोकने के लिए आए ये सुझाव

एम्स के डाक्टर अलोक ने हिमाचल में युवाओं को नशे से रोकने के लिए एक सर्वे करने का आह्वान किया गया। एनजीओ गुंजन के अजय कुमार ने बताया कि नशा निवारण केंद्रों में मुख्यतः 15 से 35 वर्ष वाले युवक अधिक आते हैं। इसके लिए प्राथमिक रोकथाम कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। गुंजन संस्था ने डिमांड रिडक्शन के लिए प्रदेश के नूरपुर, ऊना, धर्मशाला व सोलन में नशा निवारण केंद्र खोलने की जरूरत बताई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले तो लोग संस्कृति, देवी देवताओं के नाम से थोड़ा नशा करते थे परंतु अब कुल्लू जिले में हर तीसरा घर नशे की चपेट में आने की कगार पर है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बागवानी विभाग के प्रधान सचिव जेएस शर्मा ने नशे की खेती से ग्रामीणों को विमुख करने के लिए सेब, फूल व सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व अधिकारी चौहान ने भांग की खेती का उपयोग अन्य राज्यों की तरह अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए जाने की सलाह दी है। स्थानीय विधायक महेश्वर सिंह ने बताया कि गुच्छी व नाग छतरी का उत्पादन कर युवाओं को प्रेरित कर नशे का खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों औषधियों की कीमत बहुत ज्यादा है।

आखिर क्या गुल खिलाएगी वीरभद्र-धूमल की यह जंग

अब सियासी शत्रुता की बात करें , तो वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल दो विरोधी दलों के नेता होने के अलावा, एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई में भी उतरे हुए हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की नीति की शुरुआत पहले प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने ही की थी। वीरभद्र सिंह ने बाद में सत्ता में आने अपर इस परिपाटी को आगे बढ़ाया और यह जंग अब तक की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है।

देश के बड़े-बड़े राज्यों से कई क्षेत्रों में आगे निकल चुके छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों निम्न स्तर पर है। यहां की अखबारों में दो बड़े राजनेताओं के व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच चुके राजनीतिक झगड़े की खबरें छाई हुई हैं। एक-दूसरे पर लगाए जा रहे व्यक्तिगत लांछन आम आदमी को चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जिस प्रदेश की 69 फीसदी से अधिक आबादी पढ़ी लिखी हो और जहां सरकारों को बार-बार बदलने की परंपरा चली आ रही हो, वहां के राजनेताओं की सियासी जंग व्यक्तिगत शत्रुता के घटिया स्तर पर पहुंचना शायद ही जनता को पसंद आए। लिहाजा प्रदेश की जनता मौजूदा राजनीतिक बयानबाजी पर नजरें गड़ाए हुए है। यहां शर्मनाक बात यह है कि इन दोनों बड़े नेताओं की आपसी जंग में उनसे जुड़ी हुई दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुपचाप तमाशबीन की भूमिका में दिखाई दे रही हैं।

एक लड़ाई प्रदेश सरकार की छठी बार कमान संभाल रहे कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा नेता एवं नेता प्रतिपक्ष प्रो. प्रेम कुमार धूमल के बीच चल रही है। यह सियासी लड़ाई ऐसे स्तर पर है कि दोनों एक-दूसरे को जेल में भेजने को आतुर हैं। इन दोनों के लिए सत्ता में बने रहने को इनकी पार्टियों के एजेंडा से ज्यादा इनका व्यक्तिगत एजेंडा काम करता दिख रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि इनकी यह लड़ाई कोर्ट-कचहरियों से होते हुए इनके परिवारों तक पहुंच चुकी है।

वहां तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार की बात है तो इनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटा विक्रमादित्य सिंह सक्रिय राजनीति में हैं। जबकि बेटियां राजनीति से दूर हैं। वहीं प्रो. प्रेम कुमार धूमल का बड़ा बेटा अनुराग ठाकुर सक्रिय राजनीति में है, जबकि छोटा बेटा अरुण धूमल सक्रिय राजनीति से दूर है। इस सियासी जंग में प्रो. धूमल के बाद उनका छोटा बेटा अरुण धूमल ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आक्रमक और शालिनतारहित बयानबाजी करते देखा गया है।

अब सियासी शत्रुता की बात करें , तो वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल दो विरोधी दलों के नेता

होने के अलावा, एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई में भी उतरे हुए हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की नीति की शुरुआत पहले प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने ही की थी। वीरभद्र सिंह ने बाद में सत्ता में आने अपर इस परिपाटी को आगे बढ़ाया और यह जंग अब तक की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है।

इस बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश की जनता से अंतिम बार सेवा का मौका देने की भावनात्मक अपील करके सत्ता में आए हैं। प्रदेश की जनता ने भी उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की परवाह किए बिना उनके अनुभव व कार्य करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें फिर से प्रदेश की कमान सौंपी थी। सत्ता में आते ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को सरकार दस्तावेज घोषित किया तो जनता को सुशासन की उम्मीद जगी, मगर जैसे-जैसे समय व्यतित होता गया, उम्मीद पर पानी फिरता गया। वीरभद्र सिंह सत्ता की ताकत पाने के बाद फिर से अपने व्यक्तिगत राजनीतिक शत्रु धूमल परिवार को सबक सीखने की ठान चुके थे। धूमल परिवार पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने और एचपीसीए स्टेडियम व पवेलियन होटल बनाने में नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में विजिलेंस जांच खुलवा दी गई।

इस बीच केंद्र की सत्ता में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के साथ ही धूमल परिवार की स्थिति भी केंद्र में मजबूत हो गई, क्योंकि उनके खास माने जाने वाले अरुण जेटली इस बार वित्त मंत्री के महत्वपूर्ण ओहदे पर थे। वहीं अनुराग ठाकुर भी केंद्र की सत्ता का फायदा उठाते हुए बीसीसीआई सचिव बन चुके थे। हालांकि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा अभी भी उनके पास ही था। लिहाजा अब केंद्रीय जांच एजेंसियों तक धूमल परिवार की पहुंच ज्यादा मजबूत थी।

अब बारी वीरभद्र सिंह व उनके परिवार की थी। हुआ भी वैसा ही। चुनाव के समय वीरभद्र सिंह पर दर्ज मामले की जांच की फाइल खोल दी गई। अचानक वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी के दिन सीबीआई की रेड पड़ गई। इससे वीरभद्र सिंह की बेटी और परिवार को भले ही परेशानी हुई, मगर वीरभद्र सिंह को राजनीतिक संजीवनी मिल गई। इस रेड के चलते अब तक के पिछले सियासी पायदान पर पहुंच चुकी कांग्रेस को न चाहते हुए भी वीरभद्र सिंह का साथ देना पड़ा।

प्रदेश में अपनी ही पार्टी के विरोधियों के निशाने पर चल रहे वीरभद्र सिंह को हाईकमान का साथ मिलने से वे और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरे। इस मजबूती के बावजूद वे अभी भी प्रदेश की जनता को अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री नहीं दे पाए हैं। जिस जनता ने उन्हें छठी बार फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, उसकी चिंता से ज्यादा वीरभद्र सिंह को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता सताए रहती है। आरोप हैं कि उनका अधिकतर समय दिल्ली स्थित कांग्रेस दरबार में या फिर कोर्ट में व्यतीत होता है। ऐसे में उनका सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना प्रदेश की जनता को गिरावट की ओर धकेले जा रहा है। जीवन के अस्सी दशक पूरे कर चुके वीरभद्र सिंह प्रदेश की जनता के समक्ष अभी तक अपने उत्तराधिकारी तक का परिचय नहीं करवा पाए हैं और न ही वे दूसरी पंक्ति के किसी नेता को सिर उठाने देते हैं। प्रदेश की सत्ता में अभी भी वे ही सर्वेसर्वा हैं।

उधर, केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के बावजूद जब वीरभद्र सिंह कानूनी शिकंजे में नहीं कसे जा सके तो प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने अपने बयानों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की। वे सरकार गिरने की तिथि की घोषणा भी करते दिखे। इतने से काम नहीं बना तो उनके राजनीति से दूर रखे गए छोटे बेटे अरुण धूमल अपने चिर परिचित अंदाज में प्रकट होने कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के खिलाफ अखबारों में हमले बोलने लगे। इस बीच वीरभद्र सिंह इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने लगे और इससे उन्हें फायदा भी होता दिखा। उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक लग चुकी थी और धूमल परिवार का उनके गिरफ्तार होते ही सरकार गिरने का सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद शह-मात का खेल जारी रहा। तभी एक बार फिर से धूमल के छोटे पुत्र अरुण धूमल शिमला में पत्रकारों के समक्ष प्रकट हुए और ऐसा बयान जारी किया, जिसे सुन-पढ़ कर वीरभद्र व उनके प्रशंसक तो जले-भुने होंगे ही, आम आदमी भी इस बयानबाजी को पचा नहीं पा रहा था। उनके शब्द थे कि वह वीरभद्र सिंह को पंचायत का चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे...। हालांकि यह बयान उस बयान की प्रतिक्रिया था, जिसमें कहा गया था कि अरुण धूमल जिन्होंने आज तक पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ा है, वे छठी बार मुख्यमंत्री बने व्यक्ति पर सवाल उठाते आ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर प्रदेश की जनता को यह समझ नहीं आ रही कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल और राजनीति में उतरे उनके बेटे अनुराग ठाकुर के अलावा उनके राजनीति से दूर रखे गए छोटे बेटे अरुण धूमल से ऐसी बयानबाजी क्यों करवाई जा रही है। अरुण धूमल न तो भाजपा के पदाधिकारी हैं और न ही भविष्य में चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। हां बड़े भाई द्वारा एचपीसीए के नाम पर बनाई गई कंपनी में जरूर उनका नाम शामिल है।

ऐसे में क्या एचपीसीए क्रिकेट से ज्यादा धूमल परिवार की राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। या भाजपा ने एक परिवार के सामने हथियार डाल कर इसी परिवार को राजनीतिक फैसले लेने के लिए अकेला छोड़ दिया है। बरहाल जो भी हो प्रदेश की जनता इस प्रकरण पर अपने विवेक से उचित-अनुचित का निर्णय लेने का माद्दा तो रखती ही है। अब यह बात भाजपा को सोचनी है और उतना ही मंथन करने की जरूरत कांग्रेस को भी है, क्योंकि भाजपा को अगली बार सत्ता वापस चाहिए और कांग्रेस को वीरभद्र सिंह के उत्तराधिकारी की तलाश है।

-एएम अंजान

निवेशकों की पसंद भारत, बेरोजगारों की उम्मीद

देश के असंख्य बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार दो साल के भीतर दो लाख बीस हजार नौकरियों की भर्ती कर रही है। इससे भी अच्छी खबर यह है कि उभरता और मजबूत भारत निवेशकों की पहली पसंद है। भारत में सरकारी नौकरियों के प्रति आज भी खासा आकर्षण है। ग्रामीण इलाकों में तो सरकारी नौकरी प्रतिष्ठा का सवाल है। केंद्र सरकार के तहत छह लाख पद खाली रहने के बावजूद मोदी सरकार लगभग सवा दो लाख नौकरियों के लिए भर्ती करेगी। केंद्र के अधिकांश महकमे ग्रुप बी और सी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार उच्च पदों की भर्ती में तो कोई कसर नहीं छोड़ती है, मगर निचली श्रेणी के पदों को भरने में कोताही की जाती है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक पहली जनवरी 2016 के बाद से निचली श्रेणी ग्रुप डी और सी के साथ-साथ ग्रुप बी के अराजपत्रित पदों के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे। भर्ती विशुद्ध योग्यता के आधार पर की जाएगी।

प्रधानमंत्री का कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जो दो-तीन मिनट के इंटरव्यू में प्रत्याशी की योग्यता परख ले। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को ही जन्म देती है। बहरहाल, देश में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दो लाख बीस हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती से रोजगार के लिए मारे-मारे भटक रहे युवकों को काफी राहत मिल सकती है। देश में इस समय एक करोड़ से भी अधिक स्नातक, स्नाकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) और टैक्निकल ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट रोजगार की तलाश में हैं। भारत में वर्ष 1983 से 2013 के दरम्यान बेरोजगारी का औसत 7.32 फीसदी रहा है। वर्ष 2009 में यह औसत सबसे ज्यादा 9.40 फीसदी था, जबकि 2013 में बेरोजगारी की दर सबसे कम 4.90 फीसदी थी। आंकड़ों से यह जानकारी भी मिलती है कि जितनी अधिक शैक्षणिक योग्यता होगी, बेरोजगारी उतनी ही अधिक भीषण होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक निरक्षरों में बेरोजगारी की दर 7.23 फीसदी थी तो उच्च योग्यता वालों में बेरोजगारी की दर 15.78 फीसदी थी। मैट्रिक से कम साक्षरों में बेरोजगारी की दर 8.88 फीसदी थी तो मैट्रिक और स्नातक से कम पढ़े-लिखों में 14.55 फीसदी बेरोजगार थे। तथापि सुखद स्थिति यह है कि 2022 तक भारत के पास दुनिया में सबसे विशाल एक अरब वर्कफोर्स होगी और इसमें से पचास फीसदी 25 साल से कम उम्र की होगी। यही युवा फोर्स भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाएगी। जाहिर है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स को रोजगार मुहैया कराने के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक सुधारों में शिथिलता आने की वजह से रोजगार सृजन में कुछ गिरावट आई है, मगर इसके बावजूद भारत में 2015 के दौरान चीन और अमेरिका से कहीं ज्यादा विदेशी निवेश आया है। इससे रोजगार का सृजन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फोक्सकन महाराष्ट्र में पांच अरब डॉलर का कारखाना स्थापित कर रही है। इस फैक्ट्री में पचास हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि अगले एक दशक में फॉक्सकन हर राज्य में एक-एक फैक्ट्री लगाकर दस लाख रोजगार के अवसर मुहैया करा सकती है। भारत में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता का पूरा-पूरा दोहन नहीं हो पाया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में केवल 15 फीसदी का ही योगदान है। इस सेक्टर में महज 12 फीसदी वर्कफोर्स को रोजगार मिलता है। चीन में यह भारत से दोगुना 30 फीसदी है और वहां 40 फीसदी को इस सेक्टर से रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री बार-बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना का मकसद भी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को बढ़ाना है। इसलिए वे देश-विदेश के निवेशकों को भारत में कारखाने लगाने किए लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्येक परसेंटेज ग्रोथ से लगभग तीन करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इस तरह के प्रयासों से ही भारत की युवा वर्कफोर्स को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती।

-चंद्र शर्मा

"जिस तरह से विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है।"

-स्वामी विवेकानंद

इसी साल आ रही है पहली इलेक्ट्रिक बाइक

कार और स्कूटर के बाद भारत में इलेक्ट्रिक बाइक सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। टॉर्क मोटरसाइकिल कंपनी मौजूदा साल के अंत तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक पेश करेगी। पुणे स्थित ये स्टार्टअप टॉर्क नाम के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने पर काम कर रही है, जो भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी।

एक बार चार्ज करने पर चलेगी 100 किमी.

टॉर्क ने दावा किया है कि T6X एक बार चार्ज करने पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस बाइक में क्लाउड कनेक्टिविटी, फोन चार्जिंग और जीपीएस जैसी सुविधा भी दी जाएगी। T6X में लगा ऑल-डिजिटल डिस्प्ले यूनिट राइडर को जरूरत की सारी जानकारी देगा। क्लाउड कनेक्टिविटी फीचर की मदद से नजदीकी चार्जिंग स्टेशन का पता लगाया जा सकता है। कंपनी इस बाइक के प्रोटोटाइप मॉडल और सर्टिफिकेशन पर काम कर रही है। बीते दिनों इस बाइक का स्केच भी जारी किया गया था। इससे पता चलता है कि कंपनी T6X को तैयार करने पर तेजी से काम कर रही है।

2017 की पहली छमाही में शुरू होगा उत्पादन

कंपनी का कहना है कि सरकार की मदद मिले तो जल्द ही ये बाइक भारतीय सड़कों पर भागती नजर आएगी। अगर सब कुछ कंपनी की तैयारियों के हिसाब से ठीक रहता है तो टॉर्क T6X को साल के अंत तक पेश किया जा सकता है। कंपनी इसका प्रोडक्शन 2017 के पहली छमाही में शुरू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में बैंगलुरु के एथर एनर्जी नाम की कंपनी ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज को लोगों के सामने पेश किया था। ये स्कूटर जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

21 किमी. समुद्र में से गुजरेगी पहली बुलेट ट्रेन

मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए बहुत रोमांचकारी होगा। यह ट्रेन समुद्र के नीचे बनी सुरंग से गुजरेगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। इस कॉरिडोर का अधिकांश हिस्सा एलीवेटेड ट्रैक पर प्रस्तावित है। जेआईसीए की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक थाणे और विरार के बीच यह बुलेट ट्रेन 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग से गुजरेगी।

इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 97,636 करोड़ रुपए है और 81 फीसदी राशि जापान से लोन के रूप में प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट में संभावित लागत वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज और आयात शुल्क भी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि जापान 0.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 50 साल के लिए यह लोन देगा। लोन एग्रीमेंट के तहत रोलिंग स्टॉक और अन्य उपकरण जैसे सिग्नल और पावर सिस्टम का जापान से आयात किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जापान के साथ लोन एग्रीमेंट पर इस साल के अंत तक हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2018 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए रेलवे ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) नामक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन 500 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर बनी सर्च कमेटी एनएचएसआरसीएल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और पांच डायरेक्टर का चयन करने की प्रक्रिया में है। रेलवे इस स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए पहले ही 200 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। इस स्पेशल पर्पज व्हीकल में महाराष्ट्र और गुजरात की 25-25 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि शेष 50 फीसदी हिस्सेदारी रेलवे की होगी।

मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी इस बुलेट ट्रेन के जरिये तकरीबन दो घंटे में पूरी होने की बात कही जा रही है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी लगभग सात घंटे में पूरी करती है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें डीआईपीपी के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ ही रेलवे बोर्ड चेयरमैन को शामिल किया गया है।

699 से 1199 रुपए के फोन बाजार में उतारे

जाइवी मोबाइल्स-मैजिकॉन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मोबाइल डिविजन ने फीचर फोन का नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। इसमें शुरुआती कीमत 699रु. से लेकर 1199रु. के फोन हैं। शानदार स्टाइल के साथ आधुनिक तकनीक के तालमेल से बने ये फोन कम कीमत में बेजोड़ और बेहतर अनुभव लेने के इच्छुक लोगों का सच्चा साथी है। नई प्रोडक्ट रेंज की लॉन्च पर जाइवी मोबाइल्स के सीईओ पंकज आनंद ने कहा कि कंपनी को सभी के बजट में आने वाले सात नए फोन पेश करने की खुशी है। ये उनकी चाहत और जरूरत पूरा करेंगे जो बाजार में उपलब्ध महंगे फोन नहीं खरीद सकते।

जाइवी के फोन 699, 766, 849, 949, 1099 और 1199 रुपये की रेंज में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ये सारे फोन और चार्जर भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसआई) से मान्यता प्राप्त हैं। ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं जो दिल्ली में हाल में स्थापित कंपनी के संयंत्र में बनेंगे। जाइवी मोबाइल्स ने 200 करोड़ रुपये के निवेश से दो नए संयंत्र लगा कर प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना सच करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जाइवी मोबाइल्स का पहला संयंत्र नई दिल्ली के महिपालपुर में है। यह 15 हजार वर्गफुट संयंत्र उत्तर और पूर्व भारत में जाइवी मोबाइल्स की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। कंपनी के पहले संयंत्र (महिपालपुर) में प्रति माह 7 लाख मोबाइल बनाने की क्षमता है। जाइवी का दूसरा संयंत्र महाराष्ट्र के लोनावला में है। यह संयंत्र दक्षिण और पश्चिम भारत में जाइवी मोबाइल्स की मांग पूरा करेगा। आने वाले कुछ महीनों में यहां उत्पादन शुरू होगा।

फोन के साथ एलईडी बल्ब फ्री

जाइवी के हर फीचर फोन के लिए दोगुनी बचत दोगुना फायदा स्कीम के तहत 9 वाट का एलईडी बल्ब फ्री है। यह स्कीम भी नरेंद्र मोदी की स्कीम प्रकाश पथ व उजाला की ओर के अनुरूप है जिसका मकसद आम आदमी की बिजली और पैसे की बचत करना है।

वर्ष में दो बार मनाई जाती है हनुमान जयंती

वैसे तो चैत्र माह की शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन महर्षि वाल्मिकी रचित रामायण में अलग तथ्य है। इसके अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन, स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था, जो कि दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के दिन आता है। इस तरह हनुमान जी के जन्म के बारे में दो अलग दिन होने की वजह से ही हनुमान जयंती भी वर्ष में दो बार मनाई जाती है।

हनुमान जी की मां अंजना और पिता केसरी थे। उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। एक बार जब हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को अपने मुंह में रख लिया तो इंद्र देव ने उनके हनु(ठुड्डी की कोहनी) में वज्र से प्रहार किया तभी से उन्हें हनुमान नाम से संबोधित किया जाने लगा।

हनुमानजी के अन्य नाम बजरंगबली, मारुति, अंजनि सुत, पवनपुत्र, संकटमोचन, केसरीनंदन, महावीर, कपीश, बालाजी नाम भी हैं। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण करते हैं।

पूरी गरीबी खत्म करने को चाहिए 10 फीसदी ग्रोथ

वर्ष 2032 तक चाहिए 10000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत को 2032 तक 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और गरीबी पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 10 फीसदी की दर से आर्थिक ग्रोथ की जरूरत है। देश की वृद्धि दर 2015-16 में 7.6 फीसदी जबकि अर्थव्यवस्था 1700 अरब डॉलर की थी।

सिविल सेवा दिवस के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में अमिताभ कांत ने अपनी प्रस्तुति में यह भी कहा कि 10 फीसदी की वृद्धि दर से 2032 तक 17.5 करोड़ रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रस्तुती में कहा, दस प्रतिशत की दर से वृद्धि भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2032 तक 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी और कोई गरीबी नहीं होगी।

प्रशांत सागर में तथाकथित ला नीना प्रभाव से भारत में मानसून अच्छा रहने की संभावना और बारिश अच्छी रही तो देश में खपत बढ़ेगी तथा निवेश और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस साल देश को कुछ सकारात्मक आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। डॉयचे बैंक के शोध नोट में कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानी दूर करने के लिए भारत को जोरदार बारिश की जरूरत है। यह बेहतर तरीके से सभी क्षेत्रों में वितरित होनी चाहिए। इसके साथ ही ला नीना घटनाक्रम से उपभोग, निवेश और जीडीपी की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

खुद को रखना है कूल तो अपनाएं ये टिप्स

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में धैर्य नाम की चीज कहीं खो सी गई है। निजी जिंदगी हो या व्यावसायिक जिंदगी, हर कोई इससे जूझता है और खुद को कूल रखने में परेशानी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सबसे मुश्किल कामों में से एक है, खुद को शांत रखना। अगर आपमें यह क्वॉलिटी है, तो आप खुद के साथ-साथ दूसरों को भी खुश रख सकते हैं।

■ बातों को जाने दीजिए

अगर आप लोगों को बदल नहीं पा रहे हैं तो उनसे लड़ें-झगड़ें नहीं, खुद को शांत रखिए और होने दीजिए जो हो रहा है। बस चुप होकर वहां से हट जाएं। याद रखिए कि आप सही हैं या गलत इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। हर इंसान खुद को सही मानता है। कभी सोचा है कि जब आप किसी से झगड़ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि सामने वाला गलत है और सामने वाले को भी यही लगता है कि आप गलत हैं। अब जरा पक्ष बदल लीजिए। आपकी जगह सामने वाला हो और सामने वाले की जगह आप हो तो क्या झगड़ा बंद हो जाएगा? शायद नहीं।

■ गहरी सांस लें

जब कभी गुस्सा आए, तो गहरी सांस भरें फिर तेजी से छोड़ें। फिर यही प्रक्रिया धीरे-धीरे करें। आप एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे। आपका गुस्सा कुछ ही देर में कम हो जाएगा।

■ रिएक्ट न करें

तुरंत किसी की बात पर प्रतिक्रिया न दें, खासकर तब जब आप क्रोध में हों। अक्सर हम क्रोध में ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जिनसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कुछ गलत करने से पहले कई बार सोचें और सोचने के बाद भी गलत निर्णय न लें।

■ हंसते रहिए

हम सभी को हंसता-मुस्कुराता चेहरा पसंद होता है। अगर आपका चेहरा उदास या परेशान होगा, तो यह बात तय है कि आपसे कोई बात करना तो दूर, शायद देखना भी नहीं चाहेगा। हंसना एक संक्रामक चीज है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई हंसता है तो उसे देखने मात्र से हंसी आ जाती है। भले ही हमें कारण पता हो या न हो।

फिल्मों से पहले सेल्समैन थे अरशद वारसी

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी को हिंदी फिल्म जगत में कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अरशद फिल्मों में आने से पहले सेल्समैन का काम किया करते थे। हालांकि इसका कारण कमजोर आर्थिक स्थिति थी। इसके बाद अरशद ने फोटो लैब में भी काम किया। कुछ समय बाद अरशद ने डांसिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अरशद ने फिल्मी करियर साल 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से शुरू किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस रोल का ऑफर अरशद वारसी को एक्ट्रेस जया बच्चन ने दिया था। इसके बाद अरशद ने कई फिल्मों में काम किया, मगर बॉलीवुड में पहचान उन्हें साल 2003 में आई फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस और साल 2006 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से मिली। इसमें निभाए सर्किट के किरदार ने अरशद को सभी का चहेता बना दिया। अरशद को इस फिल्म के लिए अवॉर्ड भी मिला। साल 2013 में आई फिल्म जॉली एलएलबी के लिए भी अरशद को खूब तारीफ मिली।

अरशद वारसी ने साल 1987 में ठिकाना और काश फिल्म के लिए फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ बतौर असिस्टेंट भी काम किया। अरशद वारसी को शुरू से ही डांसिंग और कोरियोग्राफी में इंट्रेस्ट था। साल 1993 में अरशद वारसी को रूप की रानी चोरों का राजा का टाइटल ट्रैक कोरियोग्राफ करने का मौका मिला।

ड्रग्स से हारी रेसलर

रेसलिंग का खेल भारत में बहुत देखा जाता है। भले ही इसके नकली होने की चर्चा हो, लेकिन इसके पहलवानों के प्रति युवाओं में बहुत रुझान है। पुरुषों के प्रभुत्व वाले इस खेल में महिला पहलवान चीना के खूब चर्चे रहे। इससे लड़ने में पुरुष पहलवान भी डरते थे। शोहरत की बुलंदियां छूने वाली इस पहलवान ने 46 साल की उम्र में अपने ही घर में गुमनामी में दम तोड़ दिया। लोगों को मौत की सूचना भी सोशल मीडिया से मिली। माना जा रहा है कि ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण मौत हुई। जोआन लाउरर उर्फ चीना 15 साल की उम्र में पेशेवर रेसलर बन गई थीं। ट्रिपल एच के साथ उनकी टीम बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि टैग टीम चैंपियनशिप में वे ट्रिपल एच से भी लड़ीं। चीना ने 1999 और 2000 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत इतिहास रचा, क्योंकि ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला रेसलर थीं।

ऐसे बचाएं बच्चे को इंटरनेट के खतरों से

इस दौर के माता-पिता के पास पारंपरिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अब एक नई जिम्मेदारी भी आन पड़ी है। यह है अपने बच्चों को साइबर वर्ल्ड के खतरों से बचाने की। यदि आप अब इस आभासी दुनिया का हिस्सा होने जा रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह अपने बच्चों के साइबर अनुभव को सकारात्मक बना सकते हैं।

पहले आप इस दुनिया का हिस्सा बनें

इस खतरे से लड़ने का सबसे पहला नियम है कि आप सूचनाओं से लैस रहें। इस दुनिया में कूद जाएं और इसके आधारभूत नियमों को समझें। इससे संबंधित लेख पढ़ें, जरूरी हो तो क्लास में जाएं, दूसरे पैरेंट्स से चर्चा करें। आपको इसके लिए महारथी होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप बेसिक्स ही सीख लें। यह ही आपको मदद करेगा।

बच्चे से संवाद करें

अपने बच्चे से संवाद करें। आप उससे इंटरनेट के खतरे और फायदों की चर्चा करें। अपने बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों पर ध्यान दें। जानें कि बच्चे की पसंदीदा वेबसाइट कौन-सी है, वह कौन-से ऑनलाइन गेम्स खेलता है और इंटरनेट पर उसकी रुचियां क्या हैं? और अपने बच्चे से यह पूछने से जरा भी नहीं हिचकें कि वह किससे चैट करता है और वे आपस में किस तरह की बातें करते हैं।

बच्चे को कुछ हिदायतें दें

बच्चे को बताएं कि वह किसी भी हालत में अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अजनबी को इंटरनेट पर नहीं देगा। साथ ही यह भी कि यदि उसे इंटरनेट पर कुछ भी असुविधाजनक या आपत्तिजनक लगा तो वह तुरंत उसकी जानकारी आपको दे। अगर बच्चे को पहले ही हिदायत देंगे तो वह खुद भी सुरक्षात्मक कदम उठा सकेगा।

कंप्यूटर पर नियंत्रण रखें

ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर कुछ साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, उन्हें खोजकर उनका इस्तेमाल करें। कंप्यूटर पर बिताने के लिए समय निश्चित कर दें। बच्चे के इंस्टेंट मैसेंजर चैट को भी प्रोटेक्ट करके रखें। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप उसकी आजादी को कम कर रहे हैं बल्कि यह है कि आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं।

परिवार के साथ इंटरनेट का लाभ लें

आप अपने और अपने बच्चे के साथ-साथ परिवार को भी इंटरनेट से फायदा उठाने के लिए प्रेरित करें। इससे आपके साथ-साथ आपका परिवार भी बच्चे की वर्चुअल दुनिया पर नजर रख सकेगा। अगर परिवार के ज्यादातर सदस्य सोशल मीडिया पर हैं तो बच्चों की थोड़ी-बहुत निगरानी तो आसानी से हो ही सकती है।

सेक्सी शब्द पर भड़की सानिया

भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मीडिया में हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। दुनिया की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी सानिया एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में सेक्सी शब्द पर भड़क गईं और इसका सही मतलब बता दिया। सानिया ने सेक्सी शब्द का मतलब बताते हुए कहा-मेरे अनुसार सेक्सी का मतलब महिला को न मजबूत होना होता है न ही स्लिम और आकर्षक दिखना।

सानिया ने कहा, मेरी पहचान टेनिस से है। मेरे लिए पहले टेनिस है उसके बाद कुछ और...। अगर मेरे पास टेनिस नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूं कि अगर मैं अच्छी टेनिस नहीं खेलूंगी तो शायद ही कोई मेरी तस्वीर लेना चाहेगा। मैं एक इंसान के तौर पर काफी मजबूत हूं।

अपनी सफलता का श्रेय फिटनेस देते हुए सानिया ने कहा- टेनिस खेलने के लिए अच्छी फिटनेस का होना जरूरी है। मैं अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए खासी मेहनत करती हूं।

गौरतलब है कि एक बार सानिया से उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में एक पत्रकार ने पूछा, तो सानिया ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी को मेरे बेडरूम में झांकने का अधिकार नहीं है।

संपादक ... व प्रकाशक ... द्वारा ... सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हि.प्र. से प्रकाशित व संपादित और इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235315 Mail : badaltirahain@gmail.com